

प्रेस विज्ञप्ति
तत्काल जारी की जाने के लिए
6 सितंबर 2017

**मोदी सरकार ने मुद्रा ऋणों के जरिये 5.5 करोड़ रोजगार सृजित किए
पीएमएमवाई के कारण दो वर्षों में 1.7 करोड़ वृद्धिशील रोजगार सृजन का अनुमान**

नई दिल्ली, सितंबर 2017। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), जो लघु व्यावसायिक इकाइयों एवं उद्यमियों को संस्थागत वित्त (10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण) की सुविधा उपलब्ध कराती है, ने देश के सामने खड़ी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करते हुए केवल दो वर्षों में 5.5 करोड़ रोजगारों का सृजन किया है। स्काॅच ग्रुप की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

‘मुद्रा स्कीम : अ गेम चेंजर इनिशिएटिव ऑन जॉब क्रिएशन’ शीर्षक की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा के माध्यम से कुल 54,479,763 रोजगारों का सृजन किया गया है। इनमें 37,753,217 प्रत्यक्ष रोजगार एवं 16,726,545 अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। यह रिपोर्ट 8 सितंबर, 2017 को कांस्टीच्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 49वें स्काॅच समिट के दौरान जारी की जाएगी। स्काॅच ग्रुप के चेयरमैन एवं रिपोर्ट के लेखक श्री समीर कोचर ने कहा कि मुद्रा योजना मोदी सरकार के लिए एक छुपा रूस्तम साबित हुई है। यह देश के सामने खड़ी सबसे महत्वपूर्ण समस्या रोजगार पर ध्यान देती है।

मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य वित्त सुविधा रहित लोगों को वित्त की सुविधा उपलब्ध करानी थी।

मुद्रा योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए रिफॉर्म्स हिस्टोरियन एवं बेस्ट सेलर पुस्तक ‘मोदीनोमिक्स’ के लेखक श्री कोचर ने बताया कि मुद्रा योजना लघु उद्यमियों के सृजन पर केंद्रित है। इस योजना ने जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक उद्यमियों की एक प्रणाली सृजित की है। इसके अतिरिक्त, इसका रोजगार-सृजन पर विविध और बेहद प्रभावपूर्ण असर पड़ा है।

अभी तक 8 करोड़ से अधिक लोगों को 3.42 लाख करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं जिनमें ज्यादातर लघु उद्यमी हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो इससे पहले किसी भी प्रकार के व्यवसाय से नहीं जुड़े थे। मुद्रा ऋण 10 लाख रुपये तक के गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है। डेयरी, पॉल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कृषि से संबंध क्षेत्र भी इस योजना में शामिल हैं।

‘मुद्रा योजना: रोजगार सृजन पर एक क्रांतिकारी पहल’ अपनी तरह की ऐसी पहली रिपोर्ट है जो मुद्रा योजना के रोजगार के साथ संपर्क को रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड), बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा योजना के लाभार्थियों से भी एकत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है।

श्री कोचर कहते हैं कि ‘मुद्रा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध आंकड़े’ मुख्य रूप से खातों को खोलने एवं ऋण संवितरण से संबंधित हैं। यह रोजगार सृजन से संबंधित कोई संख्या प्रस्तुत नहीं करती। हमने ऋण के आंकड़ों को रोजगार सृजन के साथ सह-संबंध स्थापित करने के लिए व्यापक और जमीनी स्तर पर कार्य किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा योजना के बारे में एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यह समावेशी है। इसका फोकस समाज के वंचित वर्गों पर रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों की लगभग आधी संख्या वंचित वर्गों से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के 35 प्रतिशत लोग शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि, 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि यह योजना सही दिशा में लक्षित है।

इस रिपोर्ट में मुद्रा योजना के कारण रोजगारों में वृद्धिशील बढ़ोतरी पर अलग से एक खंड है। पहले दो वर्षों (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2017) के दौरान मुद्रा के कारण सृजित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगारों की कुल संख्या 11,696,576 थी। इसने 5,146,495 अप्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन को भी प्रेरित किया। इस प्रकार, दो वर्षों में सृजित वृद्धिशील रोजगारों की कुल संख्या 16,843,070 रही।

रिपोर्ट में मुद्रा योजना से संबंधित चिंताओं एवं चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। जहां यह योजना पूरी तरह लक्षित है, पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन एवं ऋण आकलन किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया गया है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण सरकारी लक्ष्यों एवं अनुमानों से अधिक रहे हैं। लक्ष्य से आगे निकलना एक उपलब्धि है और किसी भी योजना के लिए एक अच्छा संकेत है, मुद्रा योजना के साथ भी यही बात लागू होती है। बहरहाल, यह चुनौती भी पेश करती है। सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उच्च संवितरण किए गए हैं जो संभवतः लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए हैं। चूंकि ऋण संपार्श्विक (कोलेटेरल) मुक्त हैं, इसका एक समुचित जोखिम मूल्यांकन भी काफी महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक रूप से इस योजना की सफलता समुचित जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है कि इस योजना का लाभ ऐसे क्षेत्रों तथा उन लोगों तक पहुंचे, जिन तक पहुंचना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है। मुद्रा योजना के तहत संवितरित कुल ऋण में 70 प्रतिशत से अधिक 10 राज्यों में

संकेंद्रित रहा है। पारंपरिक रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों को ऋण का अधिक हिस्सा मिला है, जबकि उत्तर खासकर, पूर्वोत्तर के राज्य इस मामले में पिछड़े गए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को ऐसी योजनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे दुरुह और मुश्किल क्षेत्रों तक भी ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- 10 लाख तक के मुद्रा ऋण के कारण सृजित रोजगारों की कुल संख्या 5,44,79,763 है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा प्रदान की गई गति द्वारा सृजित वृद्धिशील, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों का कुल योग: 16,843,070
- कुल सृजित रोजगारों में से 47.77 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के तहत थे।

स्कॉच ग्रुप के बारे में:

स्कॉच ग्रुप गुरुग्राम स्थित एक थिंकटैंक है जो 1997 से ही समावेशी विकास पर फोकस के साथ सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। ग्रुप की कंपनियों में एक कंसल्टिंग विंग, एक मीडिया विंग तथा एक चैरिटेबल फाउंडेशन शामिल है। स्कॉच ग्रुप अपनी कार्यनीतियों में भारतीय भावनाओं-आवश्यकताओं का परिप्रेक्ष्य जोड़ने में सक्षम है तथा सहजतापूर्वक फॉर्च्यून-500 कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, सरकार से एसएमई तथा समुदाय आधारित संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रुप की सेवाओं के कार्यक्षेत्र भंडार में प्रक्षेत्र युक्तियां, परामर्श, अनुसंधान रिपोर्ट, प्रभाव आकलन, नीति सार, किताबें, जर्नल्स, कार्यशालाएं तथा सम्मेलन शामिल हैं। स्कॉच ग्रुप ने प्रशासन, वित्त, प्रौद्योगिकी, आर्थिकी एवं सामाजिक क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च स्वतंत्र नागरिक सम्मान (सिविलियन अवार्ड्स) का गठन किया है।

समीर कोचर के बारे में:

रिफॉर्म्स हिस्टोरियन समीर कोचर स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं। वह सामाजिक, वित्तीय एवं डिजिटल समावेश के विख्यात एवं धुरंधर पैरोकार हैं। 15 वर्ष कॉरपोरेट दुनिया में व्यतीत करने के बाद 1997 में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एक विकास विचारक बन गए। तब से ही, उन्होंने स्व-शिक्षा, शैक्षणिक अनुसंधान तथा फील्ड टूर का बीड़ा उठा लिया। स्कॉच ग्रुप, जिसके पास थिंक टैंक, मीडिया एवं कंसल्टेंसी विंग हैं— की स्थापना इन्हीं प्रयासों के एक हिस्से के रूप में की गई। सरकार उनकी विशेषज्ञता की कद्र करती है और समय-समय पर उनसे राय लेती है। श्री कोचर के विचारों, उनके लेखन एवं उनके कार्यकलापों में भारत के आर्थिक सुधारों के प्रति उनका अगाध प्रेम पूरी तरह झलकता है। इसके अतिरिक्त, उनकी लेखनी में वैसे असाधारण व्यक्तित्वों की कृतियां-जिन्होंने इन सुधारों को अधिक सार्थक और व्यापक बनाने के अनथक प्रयत्न किए-सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं:

1. अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स (2016)
2. मोदीज ओडिसी: डिजिटल इंडिया, डेवेलप्ड इंडिया (2015)
3. डिफिटिंग पॉवर्टी: जनधन एंड बियॉंड (2015)
4. मोदीनोमिक्स: इक्लुसिव इकोनोमिक्स, इक्लुसिव गवर्नेंस (2014)
5. एन एजेंडा फॉर इंडिया'ज ग्रोथ: एसेज इन ऑनर ऑफ चिदंबरम (2013)
6. पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया प्लानिंग: एसेज इन ऑनर ऑफ मोटेक सिंह अहलवालिया (2012)
7. ग्रोथ एंड फाइनेंस: एसेज इन ऑनर ऑफ सी.रंगरंजन (2011)
8. इंडिया ऑन द ग्रोथ टर्नपाइक: एसेज इन ऑनर ऑफ विजय एल केलकर (2010)
9. बिल्डिंग फ्रॉम द बॉटम: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी एलेविएशन (2010)
10. अर्बन रिन्चूवल: पॉलिसी एंड रेस्पांस (2009)
11. फाइनेंशियल इक्लुजन (2009)
12. स्पीडिंग फाइनेंशियल इक्लुजन (2009)
13. इंफ्रास्ट्राक्चर एंड गवर्नेंस (2008)

और जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

स्कॉच ग्रुप, skoch@skoch.in, +91 124 4777444